Newspaper Clips

August 11, 2012

Deccan Herald ND 18.08.2012 P-8

Nod for 20 more IIITs

A bill, which seeks to give IIITs administrative autonomy and enables setting up of 20 more such insititutes, was approved by the government on Friday, reports PTI from New Delhi.

The Indian Institute of Information Technology (IIIT) Bill, 2012 is set to be introduced during the ongoing monsoon session of Parliament, official sources said.

Once enacted, the legislation, cleared by the Union Cabinet, will confer the status of institutes of national importance on IIITs.

The establishment of each IIIT is expected cost Rs 128 crore, with the Centre bearing 50 per cent of the cost and the state government concerned 35 per cent. The remaining 15 per cent will be borne by industry partners.

Business Bhaskar ND 18/08/2012 P-1

हरी झंडी ◆ कैबिनेट ने दी आईआईआईटी बिल 2012 को मंजूरी

देश में खोले जाएंगे 20 नए आईआईआईटी

बिजनेस भास्कर/प्रेट्र • नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईआईआईटी) बिल 2012 को मंजूरी दे दी। इसके तहत मौजूदा भारतीय सूचना तकनीकी संस्थानों को प्रशासनिक स्वायत्तता दी जानी है और ऐसे ही 20 नए संस्थानों की स्थापना देशभर में की जानी है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सरकार संसद के मौजूदा सत्र में ही इस विधेयक को पेश कर सकती है। इस विधेयक के कानून बनने पर इन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिल जाएगा।

प्रत्येक आईआईआईटी की स्थापना पर करीब 128 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। इन संस्थानों की स्थापना का 50 फीसदी खर्च केंद्र सरकार देगी, जबकि 35 फीसदी बोझ संबंधित राज्य की सरकार उठाएगी। 15 फीसदी खर्च इसमें सहयोग कर रहे उद्योग जगत के साझीदार उठाएंगे।ऐसा माना जा रहा है कि कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आईआईआईटी की स्थापना में पार्टनर बनने को हरी झंडी दे दी है। फिलहाल देश में 4 आईआईआईटी हैं जो केंद्र के फंड पर चल रही हैं।ग्वालियर, इलाहाबाद, जबलपुर और कांचीपुरम में स्थित इन संस्थानों को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की योजना हर राज्य में कम से कम एक आईआईआईटी खोलने की है। इसके अलावा कैबिनेट ने उच्च शिक्षण संस्थानों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, चिकित्सा शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए संशोधनों वाले विधेयक 2010 को भी मंजूरी दे दी। यह बिल भी चालू सत्र में पेश किया जा सकता है। इसके तहत सार्वजनिक फंड से संचालित संस्थानों के लिए आरक्षण प्रावधानों आदि को अनिवार्य रूप से सार्वजनिक करने जैसी बातें शामिल हैं।ये संशोधन उन छात्रों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित कर सकेंगे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी पृष्ठभूमि से आते हैं।

तैयारी

- हर राज्य में कम से एक आईआईआईटी खोलने की योजना
- संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश किया जा सकता है विधेयक

केंद्र-राज्य मिलकर उठाएंगे खर्च

प्रत्येक नए आईआईआईटी की स्थापना पर करीब 128 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है। इन संस्थानों की स्थापना का 50 फीसदी खर्च केंद्र सरकार देगी, जबकि 35 फीसदी बोझ संबंधित राज्य की सरकार उठाएगी। 15 फीसदी खर्च इसमें सहयोग कर रहे उद्योग जगत के साझीदार उठाएंगे। माना जा रहा है कि कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आईआईआईटी की स्थापना में पार्टनर बनने को हरी झंडी दे दी है।

Hindustan ND 18/08/2012 P8

कैबिनेट ने विधेयक को दी मंजूरी, इससे इन संस्थानों को मिलेगी काम की स्वतंत्रता

खुलेंगे 20 और ट्रिपल आईटी

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

ट्रिपल आईटी को प्रशासनिक स्वायत्तता देने और 20 और ऐसे संस्थानों की स्थापना के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को एक विधेयक को मंजूरी दे दी।

विधेयक लागू होने पर आईआईटी की भांति ट्रिपल आईटी भी स्वतंत्र रूप से अपना कामकाज चलाएंगे और इन्हें राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा भी मिलेगा।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विधेयक 2012 संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। देशभर में 20 नए ट्रिपल आईटी निजी क्षेत्र की भागीदारी पर खोले जा रहे हैं।

प्रत्येक आईआईआईटी की स्थापना पर 128 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। केंद्र सरकार आधा और संबंधित राज्य सरकार 35 फीसदी खर्च उठाएगी।

शेष 15 फीसदी खर्च इसमें सहभागिता करने वाले औद्योगिक घराने उठाएंगे और जिन राज्यों में औद्योगिक घराने नहीं हैं, वहां सरकारी कंपनियां इसमें निवेश कर सकेंगी।

नए संस्थानों की स्थापना के लिए सरकार पहले ही बजट का आवंटन कर चुकी है। अभी ग्वालियर, इलाहाबाद जबलपुर और कांचीपुरम में चल रहे चार ट्रिपल आईटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल है और ये पूरी तरह से सरकारी सहायता पर चल रहे हैं।

संशोधन विधेयक भी मंजूर

कैबिनेट ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालय विधेयक 2010 में अनुचित कार्यप्रणाली निरोधक विधेयक में संशोधनों को मंजूरी दे दी। यह विधेयक संसद में पेश हो चुका है। लेकिन समिति की कुछ सिफारिशों को शामिल किया गया है।

कैबिनेट के फैसले

- राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिलेगा, 128 करोड़ होंगे खर्च
- आधा खर्च केंद्र, 35 फीसदी राज्य, 15 फीसदी सहभागी कंपनियां उठाएंगी

वेतन, भत्ते का होगा भुगतान

कैबिनेट ने लांल इमली और धारीवाल ब्रांड से ऊनी वस्त्र बनाने वाली सरकारी कंपनी ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन के चालू वित्त वर्ष के वेतन, भत्ते और अन्य खर्चों के भुगतान को मंजूरी दी है। कंपनी के 2012-13 के वेतन, भत्ते एवं अन्य खर्चे वहन करने की अनुमति देने के साथ कंपनी के अतिरिक्त कर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को 17.10 करोड़ मुहैया कराए जाएंगे।

Rashtriya Sahara ND 18/08/2012 P-2

आईआईआईटी को मिलेगी प्रशासनिक स्वायत्तता

20 और आईआईआईटी स्थापित करने के विधेयक को मंजूरी

नई दिल्ली (एसएनबी)। आईआईआईटी को प्रशासनिक स्वायत्तता देने एवं 20 और ऐसे संस्थानों की स्थापना के लिए सरकार ने शुक्रवार को एक विधेयक को मंजूरी दी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विधेयक 2012 संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने के बाद विधेयक लागू हो जाएगा और आईआईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिल जाएगा। प्रत्येक आईआईआईटी की स्थापना पर 128 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है, केंद्र सरकार आधा खर्च उठाएगी और संबंधित राज्य सरकार 35 फीसद खर्च उठाएगी। शेष 15 फीसद खर्च इसमें सहभागिता करने वाले औद्योगिक घराने उठाएंगे।

समझा जाता है कि कैबिनेट ने पीएसयू को आईआईआईटी की स्थापना में सहयोगी बनने की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार फिलहाल चार मे से तीन आईआईआईटी को वित्तीय सहायता दे रही है। ग्वालियर, इलाहाबाद, जबलपुर और कांचीपुरम को फिलहाल डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल है। सूत्रों ने कहा कि प्रत्येक राज्य में एक आईआईआईटी की स्थापना की योजना है। कैबिनेट ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालय विधेयक 2010 में अनुचित कार्यप्रणाली निरोधक विधेयक में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इन संशोधनों में वित्तपोषित संस्थानों में आरक्षण के प्रावधानों का खुलासा करना भी शामिल है। सूत्रों ने कहा कि संशोधनों से छात्रों के हितों का संरक्षण खासकर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े छात्रों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित होगा। कैबिनेट ने संसद की स्थायी समिति की अनुशंसाओं के बाद आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दी।

राजमार्ग निर्माण के लिए मॉडल दस्तावेज को मंजूरी : सड़क परियोजनाओं में अधिक समय तथा धन खर्च पर काबू पाने के लिए सरकार ने राजमार्गों के निर्माण के लिए माडल दस्तावेज को मंजूरी दी। आधिकारिक बयान के अनुसार बुनियादी ढांचे पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीआई) ने दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु प्रतिमान अभियांत्रिकी, खरीद तथा निर्माण (ईपीसी) समझौता दस्तावेज को मंजूरी दी है। यह ईपीसी दस्तावेज इस तरह से तैयार किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में अधिक समय व धन खर्च होने को कम से कम किया जा सके। बयान में कहा गया है कि जिन राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) माडल से नहीं होगा उनका निर्माण ईपीसी तरीके से होगा। अधिकार संपन्न मंत्री समूह (ईजीओएम) ने इस साल फरवरी में कहा था कि अंतर मंत्रालयी परामर्श के बाद ईपीसी दस्तावेज को सीसीआई के समक्ष रखा जा सकता है। मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले के तहत लखनादोन-घनसोर रोड परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए विशेष कंपनी (एसपीवी) बनाने की दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस काम के लिए टेलीकम्युनिकेशन कंस्लटेंट्स इंडिया (टीसीआईएल) आंतरिक संसाधनों से 23.11 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी।

कैबिनेट के फैसले

▶ उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अनुचित कार्यप्रणाली निरोधक विधेयक में संशोधन को भी मंजूरी

ब्रिटिश इंडिया के वेतन-भत्तों के भुगतान को मंजूरी : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लाल इमली और धारीवाल ब्रांड से ऊनी वस्त्र बनाने वाली सरकारी कंपनी ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के चालू वित्त वर्ष के वेतन, भत्ते और अन्य खर्चों के भुगतान को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इसके तहत कंपनी के 2012-13 के वेतन, भत्ते तथा अन्य खर्च को वहन करने की अनुमति देने के साथ ही कंपनी के अतिरिक्त कर्मचारियों को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के लिए 17.10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक के ब्याज को चुकाने के लिए 11.50 करोड़ रुपए का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

Navbharat Times ND 18/08/2012
P-14

ट्रिपल आईटी को मिलेगा राष्ट्रीय दर्जा

विशेष संवाददाता ॥ नई दिल्ली

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी (ट्रिपल आईटी) को अब राष्ट्रीय दर्जा मिल सकेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में शुक्रवार को आइआईआईटी बिल 2012 को हरी झंडी मिल गई।

इस बिल के पास हो जाने के बाद आईआईटी और एनआईटी की तर्ज पर ट्रिपल आईटी कांउसिल बनेगी। कांउसिल बनने के बाद यह स्वायत्त संस्था होगी, जो अपने प्रशासनिक और वित्तीय फैसले करने के लिए स्वतंत्र होगी। फिलहाल ट्रिपल आईटी डीम्ड इंस्टीट्यूट हैं। इस समय देश में चार ट्रिपल आईटी हैं, जो इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम हैं। इस बिल के तहत देश में 20 नए ट्रिपल आईटी का रास्ता साफ बनेगा। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सरकार का लक्ष्य हर राज्य में एक सेंटर बनाने का है। सरकार की योजना नए ट्रिपल आईटी को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर बनाने की है। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, एक आइआईआईटी पर तकरीबन 128 करोड़ की लागत का अनुमान है। जिसका 50 फीसदी केंद्र सरकार देगी और 35 फीसदी राज्य सरकार के जिम्मे होगा, जबकि 15 फीसदी संबंधित इंडस्ट्री का योगदान होगा। हालांकि सरकार की योजना प्राइवेट कंपनियों को मौका देने की थी, पर प्राइवेट कंपनियों की ओर से दिलचस्पी न दिखाने से अब सरकार इसके लिए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को भी मौका देने पर विचार कर रही है।

आईआईटी और एनआईटी की तर्ज पर ट्रिपल आईटी काउंसिल बनेगी

HT, Mumbai

PLACEMENT SEASON

IIT-B defies slowdown as salaries for students rise

Bhavya Dore
bhavya.dore@hindustantimes.com

MUMBAI: Despite the economic slowdown, placements at the Indian Institute of Technology — Bombay (IIT-B) have been better than last year.

Companies made more job offers in the highest salary bracket — which has been redefined from Rs8.5lakh and above to Rs9.5lakh and above — this year as compared to last year. The institute's final placement report was released last month.

While in 2010-11 there were 286 job offers in the Rs8.5 lakh and above annual salary bracket, in 2011-12 there were 322 offers in the Rs9.5 lakh and above annual salary bracket. There were more offers in second highest salary bracket too as compared to last year. The average annual salary

offered to students has increased from Rs7 lakh last year to Rs7.5lakh this year.

"We were pleasantly surprised as we had expected the slowdown to be far more profound," said Ravi Sinha, who was the professor in charge of placements. "There has been a maturing of the process, with companies having better engagement and more confidence and students equipping themselves better."

Even though the same number of companies visited in both years — 262 — the number of offers this year were higher, at 1,060 compared to 958 in the previous year.

The success rate for placements was best for the dual degree students at 94%, with MSc students second with 90%. Students seem happy with their placements. Nearly 40% of students surveyed from the graduating batch said they were reasonably satisfied with job offers they had got, according to data in the institute's newsletter Insight in February.

Economic Times ND 18/08/2012
P-8

SERENDIPITY

Engineering a Change in Management

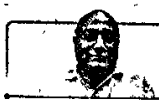

JAIDEEP MISHRA

The only thing that interferes with my learning is my education, a famous scientist is known to have quipped decades ago. That was then, when 'scientisation' and attendant rigidity in education was par for the course. Fast forward to the here and now, and the word has spread that educators at the holiest of the holy management institute, at long last, seem keen to have more non-engineers in their flagship post-graduate programme. The talk is to have a more 'diverse' student body — as over 90% of them tend to have an engineering background — which is very unlike the record at the top business schools abroad.

And about time too. It is entirely possible that the preponderance of engineers in our best management courses leads to a considerable degree of tunnel vision on the part of managers who graduate in the engineer-centric batches. The implicit idea that a background in the humanities and social sciences is generally less suited for managing people and solving their problems cannot be very convincing. Besides, in management education, as group participation in case studies, team work and projects is of vital import, a more eclectic class is more likely to enrich the overall teacher-taught experience. Yet, it is not unusual for the best pre-experience management programme here to have 95% engineers on its rolls!

One possible explanation for the strong engineering contingent could simply be the sheer practical necessity of constructing and making things in the last 50 years since the first premier institutes were set up. The high tariff barriers and other policy distortions well into the 1990s almost certainly raised the scarcity value of engineering. And the subsequent opening up and globalisation seem to have increased the premium on what used to be termed the mechanical arts, in the bid to boost manufactures and industry. In sharp contrast, in mature economies, such a perceptible skills gap is unlikely, which is why there is no extra-high premium attached to engineering education and hence in the best management programmes overseas, just about a third or less of the class tends to be engineers. Besides, engineering curriculums there in recent decades have shed their focus on scientisation, so as to be more flexible in optimising various technical, practical and societal concerns while meeting business needs.

More important, there's much flexibility built into higher education in the mature economies: there's little of the educational compartmentalisation that is a hallmark at our educational institutes. For example, at the ancient universities in the UK, most college students, no matter what course or discipline, get a uniformly-termed BA first degree (which, in due course, becomes an MA). And the tradition of dining together at those colleges can imply much scope for cross-fertilisation of ideas and opinion across subjects and topics. In the US, with its advanced tertiary system, there are myriad educational choices of course. It is not unheard of, say, to study literature as an undergraduate, then enter medical school and go on to win a Nobel prize for medicine!

Our best management programmes clearly need to be less heavily loaded with engineering talent.